रजिस्ट्री सं० डी(डी०)-73

REGISTERED No D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1979/चैत्र 3, 1901
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1979/CHAITRA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1979

का० आ० 1007—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206-बोहानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल राजाराम, ग्राम जामुनिया, पी० पडारिया, तह० गडारवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोपाल राजाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म० प्र० वि० स०/206/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 24th February, 1979

S.O. 1007.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Rajaram, Village Jamunia, P.O. Padaria, Tehsil Gadarwara, District Narsimhapur, Madhya Pradesh a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 206-Bohani constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Rajaram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/206/77]

का०आ० 1008—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 285-कोडाड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद-

वार श्री जनिमिया शेक, निवासी-मकान नं० 2-158, कोडाड, तालुक-हजूरनगर, नलगोंडा जिला, आन्ध्र प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जनिमिया शेक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं०आ०प्र०-वि०स०/285/78(15)]

S.O. 1008.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Janimia Shaik, resident of H. No. 2-158, Kodad, Taluk Huzurnagar, District Nalgonda (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 285-Kodad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Janimia Shaik to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/285/78(15)]

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1979

का०आ० 1009.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 238-डिचपल्ली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सी० नरसा रेड्डी, निवासी मकान नं० 2-3-1, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा/दाखिल करने में असफल रहे हैं;

यतः, और उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सी० नरसा रेड्डी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ० प्र०-वि० स०/238/78(16)]

New Delhi, the 27th February, 1979

S.O. 1009.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri C. Narsa Reddy, resident of House No. 2-3-1, Nizamabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 238-Dichpalli constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri C. Narsa Reddy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/238/78(16)]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का० आ० 1010.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, मनीपुर सरकार के परामर्श से श्री वाई० इबोतोम्बी के स्थान पर श्री बी० एन० श्रीवास्तव, सचिव (विधि) को उनके कार्य भार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक मनीपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/मनीपुर/78]

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 1010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Manipur hereby nominates Shri B. N. Srivastava, Secretary (Law) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Y. Ibotombi Singh.

[No. 154/MR/78]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979

का० आ० 1011.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 273-इन्दौर-4 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र सिंह, 67-अशोक नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर, (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स० म० प्र० वि० स०/273/77]

New Delhi, the 1st March, 1979

S.O. 1011.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Singh, 67, Ashok Nagar, Indore, District Indore, Madhya Pradesh a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 from 273-Indore IV consti-

tuency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/273/77]

का०आ० 1012.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 274-इन्दौर-5 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हीरालाल शास्त्री, 78-नयलखारोड, इन्दौर, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हीरालाल शास्त्री को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०वि०स० 274/77]

S.O. 1012.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hira Lal Shastri, 78-Navlekha Road, Indore, District Indore, Madhya Pradesh, a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 from 274-Indore V constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hira Lal Shastri to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/274/77]

नई दिल्ली 2 मार्च 1979

का०आ० 1013.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिल नाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2-हार्बर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वी० एस० कानन, 41, मन्डावली स्ट्रीट, मद्रास-4 (तमिल नाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(5) के अधीन सूचना नहीं भेजी जा सकी क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं था और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वी० एस० कानन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०-वि०स०/2/77(13)]

New Delhi, the 2nd March, 1979

S.O. 1013.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri V. S. Kannan, 41, Mandavalli Street, Madras-4 (Tamil Nadu), a contesting candidate for General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 2-Harbour assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the notice issued to the said candidate under rule 89(5) of the Conduct of Elections Rules, 1961, could not be served on him as his whereabouts are not known and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri V. S. Kannan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/2/77(13)]

का०आ० 1014.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 207-हिमायत नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० श्रीनिवास, मकान नं० 42/1, नालाकुन्ता, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० श्रीनिवास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ०वि०स०/207/78(17)]

S.O. 1014.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. Srinivas, H. No. 42/1, Nallakunta, Hyderabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 207-Himayatnagar constituency, has failed to lodge

the account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. Srinivas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/207/78(17)]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

शुद्धि-पत्र

का.आ. 1015—इस आयोग की तारीख 19 फरवरी, 1979 की अधिसूचना सं. 56/79 के अंग्रेजी भाग के पैरा 3 में "तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. 56/78(1)" शब्दों के स्थान पर "तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. 56/78" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 56/79(2)]

New Delhi, the 13th March, 1979

CORRIGENDUM

S.O. 1015.—In para 3 of the Commission's notification No. 56/79 dated the 19th February, 1979, for the words "56/78(1), dated 25th January, 1978" the words "56/78, dated 25th January, 1978" shall be substituted.

[No. 56/79(2)]

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1979

का०आ० 1016.—भारत के राजपत्र में तारीख 16 मार्च, 1979 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए तीन सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में—

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख	23 मार्च, 1979 (शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	24 मार्च, 1979 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम तारीख	26 मार्च, 1979 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	9 अप्रैल, 1979 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन समाप्त कर लिया जाएगा	12 अप्रैल, 1979 (बृहस्पतिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 318/केरल/79(1)]

New Delhi, the 16th March, 1979

S.O. 1016.—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India, on the 16th March, 1979, called upon the elected members of the Legislative Assembly of Kerala to elect three members to the Council of States.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election :—

(a) the 23rd March, 1979 (Friday), as the last date for making nominations ;

(b) the 24th March, 1979 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations ;

(c) the 26th March, 1979 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 9th April, 1979 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and

(e) the 12th April, 1979 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/KL/79(1)]

का०आ० 1017.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 16 मार्च, 1979 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 9 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं० 318/केरल/79(2)]

S.O. 1017.—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 9.00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 16th March, 1979.

[No. 318/KL/79(2)]

का०आ० 1018.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग केरल सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 16 मार्च, 1979 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए संयुक्त सचिव, केरल विधान मंडल सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम को रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है ।

[सं० 318/केरल/79(3)]

S.O. 1018.—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Kerala, hereby appoints the Joint Secretary to the Kerala Legislature Secretariat, Trivandrum, as the Returning Officer for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 16th March, 1979.

[No. 318/KL/79(3)]

का०आ० 1019.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख 16 मार्च, 1979 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों में रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए उप सचिव, केरल विधान मंडल सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम को नियुक्त करता है ।

[सं० 318/केरल/79(4)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 1019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary to the Kerala Legislature Secretariat, Trivandrum, to assist the Returning Officer for the Biennial Election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 16th March, 1979.

[No. 318/KL/79(4)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

का० आ० 1020.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) द्वितीय संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 की अनुसूची में शीर्ष "पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि को प्रविष्टि संख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित प्रविष्टि सं० 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उपमहानिदेशक, मौसम विज्ञान (प्रशासन एवं भंडार)/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (क्रय और भंडार)"

[फा० संख्या 23/6/78-लोक]

पी० के० कठपालिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th March, 1979

S.O. 1020.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading "Ministry of Tourism and Civil Aviation", the existing entry shall be renumbered as entry No. 1 and after entry No. 1 as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely :—

"India Meteorological Department.—Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores) / Director (Administration) / Director (Purchase and Stores)."

[F. No. 23/6/78-Public]

P. K. KATHPALIA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

का० आ० 1021—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों को जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)।

(2) राष्ट्रपति सचिवालय।

(3) कोयला विभाग।

[संख्या 12022/1/78-रा०भा०(ख-2)]

हरिबाबू कंसल, उप सचिव

New Delhi, the 13th March, 1979

S.O. 1021.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Departments, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Ministry of Railways (Railway Board).
2. President's Secretariat.
3. Department of Coal.

[No. 12022/1/78-O.L.(B-2)]

H. B. KANSAL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1979

आय-कर

का० आ० 1022.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "महाविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा।

(ii) यह कि उक्त महाविद्यालय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, विद्यानगर, जिला कैरा, गुजरात राज्य यह अधिसूचना 13-11-1978 से 12-11-1981 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2639/फा० सं० 203/165/78-आईटीए II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th January, 1979

INCOME TAX

S.O. 1022.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961,

read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'College' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) that the Birla Vishvakarma Mahavidyalaya will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agricultural/animal husbandry/fisheries & medicines),

(ii) that the said college will furnish the annual return of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Birla Vishvakarma Mahavidyalaya, Vidyanagar, District Kaira, Gujarat State.

This notification is effective for a period of three years from 13-11-1978 to 12-11-1981.

[No. 2639/F. No. 203/165/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का० आ० 1023.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि श्री गणेश अनुसंधान संस्थान, दिल्ली प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधि-कथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

श्री गणेश अनुसधान सस्थान, दिल्ली

यह अनुमोदन 10-3-1978 से 9-3-1981 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[स० 2669 (फा० सं० 203/37/78-आई टी ए II)]

New Delhi, the 19th January, 1979

S.O. 1023.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, the Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(iv) of the Income-tax Act, 1962, under the category 'Association' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) that Sri Ganesh Research Institute, Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agriculture/animal husbandry/fisheries & medicines).

(ii) That the said institute will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Sri Ganesh Research Institute, Delhi.

This approval is effective for a period of 3 years from 10-3-1978 to 9-3-1981.

[No. 2669/F. No. 203/37/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1979

का० आ० 1024.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2444, तारीख 29 जुलाई, 1978 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है ।

संस्था

प्रेमहरि अनुसंधान और विकास संस्थापन, मुम्बई

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1978 से 2 वर्ष और 9 मास की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[स० 2673 (फा० स० 203/35/78-आई टी ए II)]

New Delhi, the 23rd January, 1979

S.O. 1024.—In continuation of this Department's Notification No. 2444 dated the 29th July, 1978, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Premhari Research & Development Foundation, Bombay.

This notification is effective for a period of 2 years and 9 months from 1st July, 1978.

[No. 2673/F. No. 203/35/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1979

का० आ० 1025.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (iv) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:—

(i) यह कि केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की, प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र मे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों मे प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उ० प्र०)

यह अधिसूचना 6.11.1978 से प्रभावी होगी ।

[स० 2684 (फा० सं० 203/151/78 आई० टी० ए० II)]

New Delhi, the 25th January, 1979

S.O. 1025.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, the Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of 'Association' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) that the Central Building Research Institute, Roorkee will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agriculture/animal husbandry/fisheries & medicines).

(ii) That the said Institute, will furnish the annual return of its Scientific Research Activites to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Central Building Research Institute, Roorkee (U.P).

This notification is effective from 6-11-1978.

[No. 2684/F. No. 203/151/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1979

का० आ० 1026.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "तंत्र विद्या पीधाम" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2687/फा० सं० 197/13/78-आ०क० (ए 1)]

New Delhi, the 27th January, 1979

S.O. 1026.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Thanthra Vidya Peedham" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1973-74.

[No. 2687/F. No. 197/13/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1979

का०आ० 1027—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(1) संस्थान इस छूट के अधीन अपने द्वारा इकट्ठा की गई निधियों का पृथक हिसाब रखेगा।

(2) इस छूट के अधीन गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ, द्वारा इकट्ठा की गई निधियों का उपयोग अनन्य रूप से सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के संवर्धन के लिए किया जाएगा।

(3) यह कि संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को, एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें इस छूट के अधीन इकट्ठा की गई निधि और वह रीति जिससे निधियों का उपयोग किया गया था, दिखलाई जाएगी।

संस्था

गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

यह अधिसूचना 1-4-1977 से 31-3-1980 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2698/फा० सं० 203/148/78-आई० टी० ए० II]

New Delhi, the 30th January, 1979

S.O. 1027.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) the Institute shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

(ii) The funds collected by the Giri Institute of Development Studies, Lucknow under this exemption will be utilised exclusively for promotion of research in Social Sciences.

(iii) That the Institute shall send an Annual Report to the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

The Girl Institute of Development Studies, Lucknow.

This notification is effective for a period of 3 years from 1-4-1977 to 31-3-1980.

[No. 2698/F. No. 203/148/78-ITA. II]

शुद्धिपत्र

का० आ० 1028.—राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 200 (फा० सं० 203/18/70-आई०टी० ए० 2), तारीख 26-12-1970 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

कृपया निम्नलिखित को संस्थान के नाम के बाद जोड़ा जाए—

यह अधिसूचना, 31 मार्च, 1981 तक विधिमान्य है।

[सं० 2699/फा० सं० 203/137/78-आई० टी० ए० II]

CORRIGENDUM

S.O. 1028.—The Department of Revenue hereby amend the notification No. 200 (F. No. 203/18/70-ITA. II) dated 26-12-1970 as under :—

The following may please be added after the name of the Institute.

This notification is valid upto 31st March, 1981.

[No. 2699/F. No. 203/137/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1979

का० आ० 1029.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर

अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

यह कि प्रतिष्ठान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को, प्रत्येक वर्ष इस छूट के अधीन प्राप्त राशियों के बारे में और उन राशियों का उपयोग किस रीति से किया गया इसके बारे में एक रिपोर्ट भेजेगा।

संस्था

व्ही० शान्ताराम चलाचित्र वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति प्रतिष्ठान, मुम्बई।

यह अधिसूचना 1-4-78 से 31-3-1981 तक के तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2709/फा० सं० 203/25/78-आई०टी० ए० II]

New Delhi, the 2nd February, 1979

S.O. 1029.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions:

that the Foundation sends every year a report to the Indian Council of Social Science Research, New Delhi about the funds collected by it under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

V. Shantaram Motion Picture Scientific Research & Cultural Foundation, Bombay.

This notification takes effect for a period of 3 years from 1-4-1978 to 31-3-1981.

[No. 2709/F. No. 203/25/78-ITA. II]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1977

आय-कर

का० आ० 1030—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

(1) संस्थान, परिषद को अपने अनुसंधान क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

(2) संस्थान, अनुसंधान के लिए अनन्य रूप से प्राप्त किए गए दानों और उनके व्यय किए जाने की वार्षिक रिपोर्टें, उस रीति से, जैसी और जब परिषद अपेक्षा करें, भेजेगा।

संस्था

श्री गोविंद प्रसाद वैद्य षष्ठीपूर्ति आयुर्वेद संशोधन विज्ञान भवन न्यास, अहमदाबाद।

यह अधिसूचना, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 1713/फा० सं० 203/41/77-आई० टी० ए० II]

जे० पी० शर्मा, उप सचिव

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 5th April, 1977

(INCOME-TAX)

S.O. 1030.—In exercise of the powers conferred by clause that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions:—

(1) the institute will submit annual reports on their research activities to the Council.

(2) The institute will submit annual reports about donations received and spent exclusively for research in the manner as and when required by the council.

INSTITUTION

Shri Govind Prasad Vaidya Shashtipurti Ayurveda Samshodhan Vigyan Bhawan Trust, Ahmedabad.

This notification is effect from a period of 2 years from the date of this notification.

[No. 1713/F. No. 203/41/77-ITA. II]

J. P. SHARMA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

स्टाम्प

का० आ० 1031.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम बम्बई को, प्रोमिसरी नोटों के रूप में, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले 7 करोड़, 37 हजार रु० अंकित मूल्य के ए० आर० डी०सी० बंध पत्रों 1987 (ग्यारहवीं श्रृंखला) पर स्टाम्प शुल्क के मद्दे प्रभार्य, केवल सात लाख तीन सौ सत्तर रु० के समेकित स्टाम्प शुल्क को संदाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 13/79 स्टाम्प, फा० सं० 33/12/79-वि०क०]

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1979

STAMPS

S.O. 1031.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agricultural Refinance and Development Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of seven lakhs, three hundred and seventy rupees only, chargeable on account of the stamp duty on A.R.D.C. Bonds 1987 (Eleventh series) in the form of promissory notes of the face value of seven crores and thirty seven thousands of rupees, to be issued by the said Corporation.

[No. 13/79-Stamps-F. No. 33/12/79-ST]

का०आ० 1032—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम बम्बई को, प्रोमिसरी नोटों के रूप में, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले उन्नीस करोड़, पैंतीस हजार रुपये अंकित मूल्य के ए० आर० डी०सी० बंधपत्रों 1987 (बारहवीं श्रृंखला) पर स्टाम्प शुल्क के मद्दे प्रभार्य केवल उन्नीस लाख, तीन सौ तीस रु० के समेकित स्टाम्प शुल्क को संदाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 14/79-स्टाम्प फा० सं० 33/12/79-वि० क०]

एस० डी० रामास्वामी, अवर सचिव

S.O. 1032. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Agricultural Refinance and Development Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of nineteen lakhs and three hundred thirty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on A.R.D.C. Bonds, 1987 (Twelfth series) in the form of promissory notes of the face value of ninteen crores and thirty three thousands of rupees, to be issued by the said Corporation.

[No. 14/79-Stamps-F. No. 33/12/79-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का० आ० 1033.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध, 15 फरवरी, 1980 तक की अवधि के लिए, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचुर पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका संबंध इस बैंक द्वारा अचल सम्पत्ति अर्थात् तमिलनाडु राज्य के, कोयम्बटूर जिले के सावरीपलायम गांव में 1.63 एकड़ भूमि के टुकड़े जिसकी सर्वेक्षण संख्या 422/2 है, की धारिता से है।

[संख्या 15(2)-बी० ओ०-III/79]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 1033.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply up to 15th February, 1980 to the South Indian Bank Ltd., Trichur in respect of the immovable property viz., a piece of land measuring 1.63 Acres bearing survey No. 422/2 held by it at Savaripalayam Village, Coimbatore District, Tamil Nadu State.

[No. 15(2)-B.O. III/79]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंसिंग एरिया)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1979

रद्द करने का आदेश

का०आ० 1034.—1. मसर्स इंडियन शूगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, यमुना नगर को 54423 रुपये का आयात लाइसेंस सं० पी/एल/2801605 दिनांक 30-8-77 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने लाइसेंस सं० पी/एल/2801605 दिनांक 30-8-77 की अनुलिपि प्रतियां (केवल सीमा-शुल्क प्रयोजन) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति (केवल सीमा-शुल्क प्रयोजन) बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना और किसी भी पत्तन पर पंजीकृत कराये बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उसे रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की केवल अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए भी अनुरोध किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1978-79 की आयात तथा निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक के पैरा 354 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 के खंड 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं उपर्युक्त लाइसेंस की केवल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. अब पार्टी को 1978-79 की आयात तथा निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक के पैरा 354 में की गई व्यवस्था के अनुसार 54423 रुपये के लाइसेंस सं० पी/एल/2801605 दिनांक 30-8-77 की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० इंजी०-204/ओडी-76/ईपी-1/सीएल ए]

के० आर० धीर, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 8th March, 1979

CANCELLATION ORDER

S.O. 1034.—M/s. Indian Sugar and General Engineering Corporation, Yamuna Nagar were granted import licence No. P/L/2801605 dated 30-8-77 for Rs. 54423.

2. They have applied for duplicate copies (Custom Purposes only) of licence No. P/L/2801605 dated 30-8-77 on the ground that original (custom Purposes only) has been lost/misplaced without having been utilised at all and without having been registered with any port and have requested for cancellation thereof. The party have also requested to issue duplicate Custom purposes copy only of the aforesaid licence. They have filed affidavit in support of above statement as required under para 354 of Hand Book of Import & Export Procedures, 1978-79.

3. In exercise of the power conferred on me under Section 9(cc) of Import Control Order, 1955 dated 7th December, 1955, I order the cancellation of Custom Purpose copy only of the above mentioned licence.

4. Duplicate Custom Purposes copy of licence No. P/L/2801605 dated 30-8-77 for Rs. 54423 is now being issued separately to the party in accordance with the provision of para 354 of Hand Book Import & Exports procedure, 1978-79.

[No. Engg.-204|OD-76|EP-I'CLA]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1979-03-02

का०आ० 1035.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल०-6704 जिसके ब्यौरे नीचे दिये हैं फर्म के अनुरोध पर 1978-07-16 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गये लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-6704 1978-01-25	दि ऐक्मी पैकेजिंग इंटर प्राइजेज, ए/12 गिरिराज इंडस्ट्रियल इस्टेट महाकाली गुफा रोड, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400093	चिपकाने के कागज के टेप	IS : 4185—1967 चिपकाने के कागज के टेप की विशिष्टि

[संख्या सी एम डी/55 : 6704]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Civil Supplies & Co-operation)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1979-03-02

S. O. 1035:—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-6704 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1978-07-16 at the request of the firm :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standrads
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-6704 1978-01-25	The Acme Packaging Enterprise, A/12, Giriraj Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East, Bombay—400093	Adhesive paper tapes	IS : 4185-1967 Specification for adhesive paper tapes

[CMD/55 : 6704]

का०आ० 1036—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह), विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-1130 जिसके ब्यौरे नीचे दिये हैं 1978-07-01 से स्वामित्व और फर्म का नाम बदल जाने के कारण रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गये लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-1130 1965-08-25	सर्वोदय रेजिन वर्क्स (स्वामी : मैसर्स प्रभात जनरल एजेंसीज), जलंधर रोड, होशियारपुर (पंजाब)	बरोजा (गोंद), टाइप-पीला, मध्यम और गहरा	IS : 553—1969 बरोजा की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी एम डी/55-1130]

ए० पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक

S.O. 1036.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-1130 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 28-07-01 due to change in ownership and name of the firm :—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licenses Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-1130 1965-08-25	Sarvodaya Resin Works, (Prop. M/s. Prabhat General Agencies), Jullundur Road, Hoshiarpur (Punjab).	Rosin (gum rosin) Types—pale, medium and dark.	IS : 553—1969 Specification for rosin (gum rosin) (first revision).

[No. CMD/55 : 1130]
A.P. BANERJI, Director Dy. General

(वाणिज्यिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1979

का० आ० 1037—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन), अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लि०, रोहतक द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कंपनी को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में 28 दिसंबर, 1978 से 27 दिसंबर, 1981 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त कंपनी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[सं० 12(1)-आई टी/79]

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 7th March, 1979

S.O. 1037.—The Central Government in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Rohtak Krishna Trading Company Ltd., Rohtak and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period of three years from the 28th December, 1978 to 27th December, 1981 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said company shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(1)-IT/79]

का० आ० 1038—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन आयलसीड्स एण्ड आयल्स एक्सचेंज लि० बंबई द्वारा मान्यता का नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पत्र पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा । एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त कंपनी को मूंगफली के तेल की अग्रिम संविदाओं के बारे में 25 अप्रैल, 1979 से 24 अप्रैल, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त कंपनी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[सं० 12(2)-आई टी/79]

S.O. 1038.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bombay Oilseeds & Oils Exchange Ltd., Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years, from the 25th April, 1979 to the 24th April, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(2)-IT/79]

का० आ० 1039—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन), अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, बड़ौच द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 16 अप्रैल, 1979 से 15 अप्रैल, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाए ।

[सं० 12(3)-आई टी/79]

के० एस० मैथ्यू, उप सचिव

S.O. 1039.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of

1952), by Central Gujarat Cotton Dealers' Association, Broach, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of three years from the 16th April, 1979 to the 15th April, 1982 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the forward contracts in cotton.

[No. 12(3)-IT/79]
K. S. MATHEW, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979

का०आ० 1040.—आई० डी० आर० ए०/6/79-केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 361/आई० डी० आर० ए०/76 तारीख 5 जनवरी, 1977 के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों के स्थान पर, जिनकी पदावधि समाप्त हो गई है, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, चमड़ा और चमड़ा माल उद्योग की विकास परिषद का सदस्य संयुक्त करती है:—

1. श्री एस० एस० मराठे, सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली-110011 — अध्यक्ष

2. श्री पी० के० कौल, अपर सचिव, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, (वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली-110011 — सदस्य

3. श्री आई० महादेवन, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिकी विकास विभाग, नई दिल्ली-110011 — सदस्य-सचिव

4. श्री राम के० वेपा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 — सदस्य

5. श्री के० वी० एस० मूर्ति, संयुक्त सेलाहकार (सी० आई०), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-110001 — सदस्य

6. श्री आर० एस० घोष, विकास अधिकारी (चमड़ा), तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 — सदस्य

7. डा० ए० सी० नारामइय्या, अध्यक्ष, टेनरी और फुट वियर कारपोरेशन, 115, लक्ष्मी निवास, सातवीं ब्लाक, 28 वां क्रास, जयनगर, बंगलौर-560011 — सदस्य

8. डा० एन० रामानाथन्, भारसाधक निदेशक, केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अध्यार, मद्रास-600020 — सदस्य

9. श्री एम० एम० अनवरूल्ला, अध्यक्ष, चर्म निर्यात प्रोन्नति परिषद्, भारवल हाल, 118, वेपटी हाई रोड, मद्रास-600003 — सदस्य

10. श्री टी० एम० आर० सुब्रामनियन, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन (कारपोरेशन) निगम, हिंग की मन्डी, आगरा-282003 — सदस्य

11. श्री डी० के० घोष, मुख्य उप कार्यपालक अधिकारी (ग्राम उद्योग), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3, इरला, रोड, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई-400056 — सदस्य

12. श्री एम० एस० बैट्राबेट, समूह प्रबंधक, भारतीय जमा और विनिधान निगम, 163, बैकवे टिक्लेमेशन, मुम्बई-400020 — सदस्य

13. श्री संजय सैन, अध्यक्ष, मैसर्स नैशनल टेनरी कम्पनी लिमिटेड, प्रिनडलेज सेन्टर, 33-क, चौरिंघी रोड, कलकत्ता-700071 — सदस्य

14. श्री ई० के० एम० अब्दुल ग़नी, अध्यक्ष, इरोड स्माल टेनर्स एसोशिएशन, इरोड, तमिलनाडु — सदस्य

15. श्री बी० एम० खारत, अध्यक्ष, लैदर गुड्स मैन्युफेक्चर्स एसोशिएशन, भारतीय कला और उद्योग, 106, निर्मल इन्डस्ट्रियल एस्टेट, रोड सं० 29, सियोन, मुम्बई-400022 — सदस्य

16. श्री ए० ए० रशीद,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
मैसर्स रशि लैदर्स प्राइवेट लिमिटेड,
11—ए सिडिनेहमम् रोड,
पेरियामेट
मद्रास—600003 —सदस्य

2. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की द्वितीय अनुसूची में प्रगणित सभी कृत्य उक्त विकास परिषद् को समनुदिष्ट करती है। विकास परिषद् ऐसे अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगी जिनकी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षा की जाए।

[सं० 11/81/78—एल० आर० जी०]
आर० के० आनन्द, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1979

S.O. 1040.—IDRA/6/79.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Ragulation) Act, 1951 read with rules 2, 4 and 5 of the DevelopmentCouncil (Procedural) Rules, 1952 the Central Government hereby appoints for a period of two years with effect from the date of this order the following persons to be members of the Development Council for the Leather and Leather Goods Insdustries in place of the members appointed under Ministry of Industry (Department of Industrial Development) order No. S.O. 361/IDRA/76 dated the 5th January, 1977, whose term of office has expired :—

1. Shri S.S.Marathe, Chairman
Secretary,
Ministry of Industry,
Deptt. of Industrial Development
New Delhi-110011

2. Shri P.K. Kaul, Member
Additional Secretary,
Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation,
(Deptt. of Commerce)
New Delhi-110011

3. Shri I. Mahadevan, Member-Secretary
Joint Secretary,
Ministry of Indutry,
Deptt. of Industrial Development
New Delhi-110011

4. Shri Ram K. Vepa, Member
Development Commissioner,
Small Scale Industries.
Nirman Bhavan,
New Delhi-110011

5. Shri K.V.S. Murthi, -do-
Joint Adviser (CI)
Planning Commission,
Yojana Bhavan,
New Delhi-110001

6. Shri R. S. Ghosh, -do-
Development Officer (Leather)
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

7. Dr. A. Seetharamiah, Member
Chairman,
Tannery & Footwear Corporation,
115, Laxmi Niwas,
7th Block, 28 th Cross,
Jay Nagar,
Bangalore-560011.

8. Dr. N. Ramanathan, -do-
Director-in-charge,
Central Leather Research Institue,
Adyar,
Madras-600020

9. Shri M.M. Anawarullah, -do-
Chairman,
Leather Export Promotion Council,
Marble Hall,
118, Vepery High Road,
Madras-600003

10. Shri T.S.R. Subramaniau, -do-
Chariman,
UP State Leather Development and Markoting Corporation,
Hing Ki Mandi,
Agra-282003

11. Shri D.K. Ghosh, -do-
Dy. Chief Executive Officer (Village Industries)
Khadi & Village Industries Commission
3, Irla Road,
Vile Parle (West)
Bombay-400056

12. Shri S.S.Botrabet, -do
Group Manager,
Industrial Credit and Investment Corporation of India,
163, Backbay Reclamation,
Bombay-400020.

13. Shri Sanjoy Sen, -do-
Chairman,
M/s National Tannery Company Ltd.,
Grindlays Center,
33-A, Chowringhee Road,
Calcutta-700071

14 Shri E.K.M. Abdul Gani, -do-
President,
Erode Small Tanners Association,
Erode, Tamilnadu.

15. Shri B.M. Kharat, -do-
President,
Leather Goods Manufacturers Association,
Indian Arts and Industries,
196, Nirmal Industrial Estate,
Road No. 29, Sion,
Bombay-400022.

16. Shri A.A.Rasheed, -do-
Chairman & Managing Director,
M/s Rashi Leathers Pvt. Ltd.,
11-A, Sydenhams Road,
Perianet,
Madras-600003

2. The Central Government hereby assings all the functions enumerated in the Second Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, to the said Development Council . The Development Council shall also perform such other functions as it may be required to perform by or under any other provisions of the Act.

[No.11/81/78-LRG]
R.K. ANAND, Director

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1979

का० आ० 1041.—हज समिति, बंबई के गठन के बारे में इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम(हज))118-1/2/77 दिनांक 17 नवंबर, 1977 के क्रम में बंबई नगर निगम, ग्रेटर बम्बई के निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम हज समिति, बंबई के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किए जाते है :—

(1) डा० अलीमोहमद उमर मेमन

(2) श्री अशरफी अब्दुल रहमान सूफी

[सं० एम(हज)118-1/2/77]
वी० के० ग्रोवर, संयुक्त सचिव (हज एवं वाना)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th March, 1979

S.O. 1041.—In continuation of this Ministry's Notification No. M(Haj) 118-1/2/77 dated the 17th November, 1977 regarding the constitution of the Haj Committee, Bombay, names of the following two members of the Bombay Municipal Corporation of Greater Bombay, area notified as members of the Haj Committee, Bombay :—

(1) Dr. Alimohamed Umar Memon.

(2) Shri Ashrafi Abdul Rehman Soofi.

[No. M(Haj)118-1/2/77]
V. K. GROVER, Jt. Secy. (Haj & Wana)

(कौंसली अनुभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का० आ० 1042.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत के राजदूतावास, डक्कर, सेनेगल में सहायक, श्री एल० मी० वजीरेन को तत्काल से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं० टी-4330/1/79]
जे० हजारी, अवर सचिव

(Counsular Section)

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 1042.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Counsular Officers (Oath & Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri L. C. Vazirani, Assistant in the Embassy of India, Dakar, Senegal to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect

[No. T. 4330/1/79]
J. HAZARI, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का० आ० 1043.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनीज पाईप लाईन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कडी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० जे० एल० एल० से जी० जी० एम० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 10-2-1978 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

जे० एल० एल० से जी० जी० एम० तक पाईपलाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	मेरडा	3550	9-12-1978	10-2-1978

[सं० 12016/15/79-प्रो०-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 1043.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S JLL to GGS in Kadi oil field in Gujarat State;

And Whereas the oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 10-2-1978.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 the Competent (Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. JLL To GGS

Name of Ministry	Villages	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum Chemicals & Fertilizer	Merda	3550	9-12-1978	10-2-1978

[No. 12016/15/79-Prod-I]

का० आ० 1044.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कदी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० एस—12 से एस—12 के पास जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 30-8-1977 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एस०—12 से एस—12 के पास जी० जी० एस० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	मेरडा	3358	25-11-1978	30-8-1977

[सं० 12016/15/79—प्रो०—II]

S.O. 1044—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. S–12 to GGS near S–12 to in Kadi oil field in Gujarat State.

And Whereas the oil & Natural Gas Commission has terminated the oprations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 30-8-1977.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D S. S–12 to GGS NEAR S–12

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	MERDA	3358	25-11-1978	30-8-1977

[No. 12016/15/79-Prod-II]

का० आ० 1045.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कदी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० एस० जी० पी (एस—54) से जी० जी० एस० सानंद-12 के पास तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 12-12-1977 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एस० जे० पी० एस०—54 से जी० जी० एस० सानंद—12 के पास तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	आद्रज मेरडा	3449	2-12-1978	12-12-1977

[सं० 12016/15/79-प्रो०-III]

S.O. 1045.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SJP (S-54) to GGS ATSANAND-12 in Kadi oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 12-12-1977.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user of land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination fof Operation of Pipeline From D.S. SJP (S-54) to GGS at Sanand-12

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	ADRAJ MERDA	3449	2-12-1978	12-12-1977

[No.12016/15/79-Prod.III]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1979

का० आ० 1046—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात

राज्य के डबका तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० डबका जी० सी० एस० से ए० बी० जी० एल० वी० पी० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 25-6-1978 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

डबका जी० सी० एस० से ए० बी० जी० एल० वी० पी० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन मोभा और उर्वरक		149	13-1-1979	25-6-1978

[सं० 12016/17/79-प्रोड-I]

New Delhi, the 3rd March, 1979

S.O. 1046.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acqulsition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from DABKA GCS to ABGL V.P. in Dabka oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated tjo operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 25-6-1978.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from DABKA GCS to ABGL V.P.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	MOBHA	149	13-1-1979	25-6-1978

[No. 12016/17/79-Prod-I]

का० आ० 1047.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० के०ओ०डी०-3 से के०सी०ई० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 29-10-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

के०ओ०डी०-3 से के०सी०ई० तक पाइन लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	प्रतापपुरा ओला कलोल	3450	2-12-1978	29-10-78

[सं० 12016/16/79—प्रोड-1]

S.O. 1047.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KOD-3 to KCE in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Action 29-10-76.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. KOD-3 to KCE

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	PRATAP-PURA OLA KALOL	3450	2-12-1978	29-10-1976

[No. 12016/16/79-Prod-I]

का०आ० 1048.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० के०ई०एक्स-4 से के-7 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 18-3-1976 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

के०ई०एक्स से के-7 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	सेरथा	3540	9-12-1978	18-3-1976

[सं० 12016/16/79-प्रोड-II]

S.O. 1048.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KEX-4 to K-7 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act in 18-3-1976

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. KEX-4 to K-7.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	SERTHA	3540	9-12-1978	18-3-1976

[No. 12016/16/79-Prod-II]

का०आ० 1049.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनीज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० सानन्द-49 से सानन्द-18 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 18-1-1976 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

सानन्द-49 से सानन्द-18 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	खातज	3548	9-12-1978	18-1-1976

[सं० 12016/16/79-प्रोड-III]

S.O. 1049.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Sanand-49 to Sanand-18 in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 18-1-1976.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SANAND-49 To SANAND-18

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	KHAT-RAJ	3548	9-12-1978	18-1-1976

[No. 12016/16/79-Prod-III]

का०आ० 1050.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनीज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० के-115 से सी०टी०एफ० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 4-4-1974 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूचि

के-115 से सी०टी०एफ० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	सईज	3546	9-12-1978	4-4-1974

[सं० 12016/16/79-प्रोड-IV]

S.O. 1050—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. K-115 to C.T.F. in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 4-4-1974.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. K-115 to C.T.F.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	SAIJ	3546	9-12-1978	4-4-1974

[No. 12016/16/79-Prod.-IV]

का०आ० 1051—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनीज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० जी०जी०एस० VIII से सोक ओइल०टी० कनेक्सन तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 6-12-1978 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

जी०जी०एस० VIII से सोक ओइल-टी० कनेक्सन तक पाइप लाइन

कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	कलोल.. बोरीसना	3919	17-12-1977	6-12-1978

[सं० 12016/16/79-प्रोड-V]

S.O. 1051—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from G.G.S. VIII to SOKOIL TEE CONNECTION in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 6-12-1978.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from G.G.S. VIII to SOKOIL TEE CONNECTION

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	KALOL BORI-SANA	3919	17-12-1977	6-12-1978

[No. 12016/16/79-Prod.-V]

का० आ० 1052—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनीज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० के० ई० एक्स-7 (के-161) से के-136 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन कर लिया है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक जुलाई 1975 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूचि

...-161) से के-136 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	पुनद्रासन अवारसद	150	13-1-1979	जुलाई-1975

[सं० 12016/16/79-प्रोड-VI]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

S.O. 1052.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KEX-7 (K-161) to K-136 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on July, 1975.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. KEX-7 (K-161)

To K-136

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	PUNDRASAN UVARSAD	150	31-1-1979	July, 1975

[No. 12016/16/79-Prod.-VI]

for

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1979

का०आ० 1053—13 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3, उपखंड (2) में का०आ० 157 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 4 अगस्त, 1978 की अधिसूचना संख्या एस० 14025/8/78-एम—एस० को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

[संख्या एस० 14025/8/78-एम०एस०]

एन०ए० सुब्रामोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 7th March, 1979

S.O. 1053.—The notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S. 14025/8/78-MS, dated the 4th August, 1978, published as S.O. 157, in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated the 13th January, 1979, is hereby cancelled.

[No. S. 14025/8/78-MS]

N. A. SUBRAMONEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

का०आ० 1054.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 (1956 का 25) के खण्ड-4 की धारा (ङ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री राजनारायण के स्थान पर डा० पाई पनन्दीकर, निदेशक, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के एक सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 24 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० वी० 16011/1/76-एम०ई० (पी०जी०) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात् :—

"1. डा० पाई पनन्दीकर,
निदेशक,
नीति अनुसंधान केन्द्र,
नई दिल्ली "।

[सं० वी० 16011/2/78-एम०ई० (पी०जी०)]

आर०वी० श्रीनिवासन, उप-सचिव

New Delhi, the 13th March, 1979

S.O. 1054.—In pursuance of clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Dr. Pai Panandiker, Director, Centre for Policy Research, New Delhi, to be the member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi vice Shri Raj Narain and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 16011/1/76-M.E. (PG) dated the 24th December, 1977, namely :—

In the said notification, for entry 1, the following entry shall be substituted namely :—

"1. Dr. Pai Panandiker,
Director,
Centre for Policy Research,
New Delhi."

[No. V. 16011/2/78-M.E.(PG)]

R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

आदेश

का०आ० 1055—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि इस आदेश की अनुसूची के भाग I और भाग II के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" और साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" पदों की बाबत स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तम्भ 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासन-प्राधिकारी और अपील-प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वह (नियम II के मद सं० 7 के संबंध में) अधिरोपित कर सकता है		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
भाग I—साधारण सेवा, समूह "ग"				
सभी पद	प्रोग्राम अधिकारी, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	प्रोग्राम अधिकारी, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	सभी	संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली ।
भाग II—साधारण सेवा समूह "घ"				
सभी पद	प्रोग्राम अधिकारी, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	प्रोग्राम अधिकारी, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	सभी	संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (कृषि विभाग), नई दिल्ली ।

[सं० 1-35/78-एफ आर वाई-1]

जी० एन० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 9th March, 1979

ORDER

S.O. 1055.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service, Group C and the General Central Service, Group D, specified in column 1 of Parts I and II of the schedule to this order the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the Disciplinary Authority and Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Description of post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in 7 rule 11)		Appellate authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
PART I—General Central Service, Group C				
All posts . . .	Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.	Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.	All	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Department of Agriculture), New Delhi.
PART II—General Central Service, Group 'D'				
All posts . . .	Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.	Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.	All	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), New Delhi.

[No. 1-35/78-FRY-1]

G.N. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

का०आ० 1056.—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं को पकड़ना) नियम, 1978 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) के खण्ड (i) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० 14-19/76-एल०डी० 1, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 13 जनवरी, 1979 के पृष्ठ 139-140 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र 13 जनवरी, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम क्रूरता निवारण (पशुओं का पकड़ना) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पक्षियों को पकड़ना—किसी भी पक्षी को विक्रय, निर्यात या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जाल पद्धति को छोड़कर किसी अन्य पद्धति द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—किसी पक्षी को जाल पद्धति द्वारा पकड़ा गया तब कहा जाएगा जब उसके पकड़ने में निम्नलिखित युक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात्—ऐसी युक्ति जो सूत, जूट या किसी संश्लिष्ट तंतु जैसे किसी मुलायम, लचकदार और पर्याप्त रूप से मजबूत बने हुए धागे से उपयुक्त आकार की जाली के रूप में इस प्रकार बुनी गई है कि पक्षी को बिना कोई क्षति पहुंचाए पकड़ा जा सके ।

3. अन्य पशुओं को पकड़ना—(1) किसी भी पशु को विक्रय, निर्यात या किसी अन्य प्रयोजन के लिए बोरी और फन्दा पद्धति को छोड़कर किसी अन्य पद्धति द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा;

परन्तु यदि किसी पशु को उसके आकार, प्रकृति या अन्य बात या परिस्थिति के कारण बोरी और फन्दा पद्धति द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है तो उसे प्रशांतक बन्दूक या किसी ऐसी अन्य पद्धति द्वारा पकड़ा जा सकता है जिससे पकड़े जाने से पहले, वह पीड़ा के प्रति असम्वेदनशील हो जाए ।

(2) इस नियम की कोई बात पक्षियों के पकड़े जाने को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—किसी पशु को बोरी और फन्दा पद्धति द्वारा पकड़ा गया तब कहा जाएगा जब उसके पकड़ने में निम्नलिखित युक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात् बोरी के आकार का एक मजबूत कैनवस, जो लम्बाई में 92 से० मी० और व्यास में 138 से० मी० से कम नहीं है, जिसमें एक मुलायम रस्सी लगी है जो लम्बाई में 5.5 मीटर से कम नहीं है और कम से कम 4 से० मी० व्यास के दस या दस से अधिक ऐसे छल्लों में से निकाली गई है जो बोरी के खुले सिर पर लगे हैं और जिनसे फन्दा बना है । बोरी में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे-छोटे छिद्र होंगे जिससे पशु बंदी की स्थिति के दौरान श्वास ले सके और पशु को, उस पर बोरी फेंक कर तथा फन्दा कस कर पकड़ा जा सके ।

[सं० 14-19/76-एल०डी० 1]

बी० बी० कपूर, उप सचिव

New Delhi, the 13th March, 1979

S.O. 1056.—Whereas a draft of the Prevention of Cruelty to Animals (Capture of Animals) Rules, 1878 was published as required by clause (i) of Sub-section (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), at pages 139-140 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 13th January, 1979 under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) No. 14-19/76-LD. I dated the 30th December, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th January, 1979;

And whereas no objections and suggestions from the public on the said draft have been received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Prevention of Cruelty (Capture of Animals) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Capture of birds.—No bird shall be captured for the purpose of sale, export or for any other purpose except by the net method.

Explanation.—A bird is said to be captured by the net method it in its capture the following contrivance is used, namely, a contrivance made of spun thread which is soft, pliable and sufficiently strong, like cotton, jute or any synthetic fibre, woven in such a way as to form a mesh of suitable size so that the bird is captured without any injury being caused to it.

3. Capture of other animals.—(1) No animal shall be captured for the purpose of sale, exported or for any other purpose except by sack and loop method :

Provided that an animal which cannot be captured by reason of its size, nature or other condition or circumstance by the sack and loop method, may be captured with the help of tranquiliser guns or by any other method which renders the animal insensible to pain before capture.

(2) Nothing in this rule shall apply to the capture of birds.

Explanation.—An animal is said to be captured by the sack and loop method it in its capture the following contrivance is used, namely, a strong canvass in the form of a sack, not less than 92 cms. in length and 138 cms. in diameter, which has a smooth rope, not less than 5.5 meter in length passing through ten or more rings of not less than 4 cms. in diameter each attached at the open end, thus forming a loop, the sack having small holes at convenient places to enable the anmial to breathe during captivity, and the animal is captured by the sack being thrown on it and **secured by having the loop pulled.**

[No. 14-19/76-LD-I]

B. B. KAPUR, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1979

का० आ० 1057.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में, कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कार्यालय, (राजस्व विभाग) बिर्येसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर में या कलेक्टर, बेतूल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 7 में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि०; बिर्येसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर-1 को भेजेंगे ।

अनुसूची

धसेर ब्लाक (सतपुरा-III)

पठखेड़ा कोयला क्षेत्र

रेखांक सं०-डब्ल्यू० सी० एल०/पी० एल० जी०/सी० 1 (ई) III एफ० एफ० आर०/113-11-78 तारीख 21-11-78 (जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित की गई है)

अनुसूची "क"

क्रम सं०	ग्राम	प० स० सं०	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	पठखेड़ा	27	बेतूल	बेतूल	..	भाग
2	घोगरी	25	यथोक्त	यथोक्त	..	भाग
3.	धसेर	25	यथोक्त	यथोक्त	..	भाग
4.	बगदोना	23	यथोक्त	यथोक्त	..	भाग

कुल क्षेत्र : 750.00 हेक्टेयर (लगभग)
या 1852.50 एकड़ (लगभग)

अनुसूची "ख"

क्रम सं०	वन का नाम	कोष्ठ सं०	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	रानीपुर आरक्षित वन	380	बेतूल	बेतूल	..	भाग
2.	यथोक्त	381	यथोक्त	यथोक्त	..	भाग
3.	यथोक्त	382	यथोक्त	यथोक्त	..	भाग

कुल क्षेत्र : 725.00 हेक्टेयर (लगभग)
या 1790.75 एकड़ (लगभग)

अनुसूची "ग"

क्रम सं०	भूमि के स्वामी का नाम	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का सरनी उष्मीय शक्ति गृह	बेतूल	बेतूल	..	भाग

कुल क्षेत्र 730.00 हेक्टेयर (लगभग)
या 1803.10 एकड़ (लगभग)

अनुसूची क, ख और ग का कुल जोड़ 2205.00 हेक्टेयर (लगभग)
या
5446.35 एकड़ (लगभग)

सीमा विवरण

क-ख	रेखा, धसेर गांव से होती हुई बगदोना गांव में बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
ख-ग	रेखा, रेल भूमि की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बगदोना गांव से होती हुई राजस्व और आरक्षित वन भूमि की सीमा पर बिन्दु "ग" पर मिलती है।
ग-घ-ङ	रेखा, रानीपुर आरक्षित वन और बगदोना गांव की सामान्य सीमा के साथ-साथ होती हुई बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
ङ-च-छ	रेखा, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,
ज-झ-ञ	1957 की धारा 9(1) के अधीन पहले से अधि-
ट-ठ-ड	सूचित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ
ढ-ण-त	होती हुई बिन्दु "त" पर मिलती है ।
थ-द-ध	
न	
त-प	रेखा, म० प्र० वि० बो० को अन्तरित किए गए वन क्षेत्र से होती हुई पठखेड़ा गांव में बिन्दु "प" पर मिलती है।
प-क	रेखा पठखेड़ा, घोगरी गांव से होती हुई धसेर गांव में आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19(4)/79-सी० एल०]
एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 8th March, 1979

S.O. 1057.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur or at the Office of the Collector, Betul (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1 within ninety days from due date of publication of this notification.

SCHEDULE

DHASER BLOCK (SATPURA-III)

PATHAKHERA COALFIELD

Drawing No. WEL/PLG/C-1 (E) III/FFR/113-II/78

Dated 21-11-1978

SCHEDULE "A"

(Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Village	P. C. No.	Tahsil	District	Area	Remarks
1.	Pathakhera	27	Betul	Betul	—	Part
2.	Ghogri	25	,,	,,	—	Part
3.	Dhaser	25	,,	,,	—	Part
4.	Bagdona	23	,,	,,	—	Part
		Total Area :	750 00 hectares (approximately)			
		OR	1852.50 acres (approximately)			

SCHEDULE "B"

Sl. No.	Name of Forest	Compartment No.	Tahsil	District	Area	Remarks
1.	Ranipur Reserve Forest	380	Betul	Betul	—	Part
2.	-do-	381	,,	,,	—	Part
3.	-do-	382	,,	,,	—	Part
		Total Area :	725.00 hectares (approximately)			
		OR	1790.75 acres (approximately)			

SCHEDULE "C"

Sl. No.	Name of Owner of land	Tahsil	District	Area	Remarks
1.	Sarni Thermal Power House of Madhya Pradesh Electricity Board.	Betul	Betul	—	Part
	Total Area :	730.00 hectares (approximately)			
	OR	1803.10 acres (approximately)			
	Grand Total of Schedules A,B, and C.	2205.00 hectares (approximately)			
	OR	5446 35 acres (approximately)			

Boundary Description :

A—B . . . Line passes through village Dhaser and meets in village Bagdona at point 'B'.

B—C . . . Line passes through Village Bagdona along the southern boundary of the Railway's land and meets on the boundary of Revenue and Reserve forest land at point 'C'.

C—D—E . . Line passes along the common boundary of Ranipur Reserve forest and Bagdona village and meets at point 'E'.

E—F—G—H—I—J—K—L—M—N—O—P—Q—R—S—T Line passes along the Southern boundary of the area already notified u/s. 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and meets at point 'T'.

T—U . . . Line passes through the Forest area transferred to MPEB and meets in village Pathakhera at point 'U'.

U—A . . . Line passes through village Pathakhera, Ghogri and meets in village Dhaser at the starting point 'A'.

[No. 19(4)/79-CL]

S. R. A. RIZVI, Director

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1979

का०आ० 1058.—नेशनल शिपिंग बोर्ड रूल्स, 1960 के नियम 3 के साथ पठित मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 1452 दिनांक 20 मई, 1978 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० पद्मनाभन, उप महानिदेशक, नौवहन को श्री एम० वाला के स्थान पर जो अपने मूल कार्यालय वापस चले गये हैं, 1 मार्च, 1979 से नेशनल शिपिंग बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है ।

[संख्या एम०एस०बी०-10/77(एम०एफ०)]
एन०डी० मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 6th March, 1979

S.O. 1058.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960 and in supersession of paragraph 2 of the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification S. O. No. 1452 dated 20-5-1978, the Central Government hereby appoints Shri R. Padmanabhan, Deputy Director General of Shipping, as Secretary of the National Shipping Board with effect from the 1st March, 1979, vice Shri M. Wala, who reverted to his parent department.

[No. MSB-10/77(MF)]
N. D. MALHOTRA, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली 20 फरवरी, 1979

का०आ० 1059.—पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अनअथोराइज्ड ओक्यूपेंट्स) ऐक्ट, 1971 (40 आफ 1971) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस०ओ० 1696 दिनांक 21 मई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में कालम (2) के सामने दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा :—

"भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित अथवा उसके द्वारा लीज पर ली गई और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में स्थित सभी सम्पत्तियां, निम्नलिखित को शामिल करते हुए:—

अशोक होटल, 50-बी०, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली; जनपथ होटल, जनपथ, नई दिल्ली; लोधी होटल, लाला लाजपत राय मार्ग, नई दिल्ली; होटल रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली; अकबर होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली ; कुतुब रेस्तरां कुतुब दिल्ली प्लाट नं० 119, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली; कुतुब होटल, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ; विन्डसर प्लेस होटल, 17 अशोक रोड, नई दिल्ली और अशोक यात्री निवास, 19, अशोक रोड, नई दिल्ली।"

[संख्या यू-11015/6/78-पी०एम०यू० (पर्यटन)]
बानू राम अग्रवाल, उप-सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 1059.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 1696 dated the 21st May, 1975, namely :—

In the Table to the said notification, for the entries under column (2), the following entries shall be substituted, namely :—

"All properties belonging to or taken on lease by the India Tourism Development Corporation Limited and situated in the Union Territory of Delhi, including the following :—

Ashoka Hotel, 50-B, Chanakyapuri, New Delhi; Janpath Hotel, Janpath, New Delhi; Lodi Hotel, Lala Lajpat Rai Marg, New Delhi; Hotel Ranjit, Maharaja Ranjit Singh Road, New Delhi; Akbar Hotel, Chanakyapuri, New Delhi; Kutub Restaurant, Kutab, Delhi Plot No. 119, Naraina Industrial Estate, New Delhi; Qutab Hotel, Off Sri Aurobindo Marg, New Delhi; Windsor Place Hotel, 17, Ashoka Road, New Delhi and Ashok Yatri Niwas, 19, Ashoka Road, New Delhi."

[No. U-11015/6/78-PSU (Tourism)]
BANU RAM AGGARWAL, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1979

का०आ० 1060.—चलचित्र (सेंसरशिप) नियमावली, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश के संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के० स्वामीनाथन को 18-1-1979 के अपराह्न से अगले आदेश तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के प्रादेशिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है ।

[फा० सं० 2/47/78-एफ०सी०]
के० एस० वेंकटरामन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd March, 1979

S.O. 1060.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to appoint Shri K. Swaminathan, an officer of the Indian Administrative Service borne on the Andhra Pradesh Cadre, to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras with effect from 18-1-1979 A.N. until further orders.

[F. No. 2/47/78-FC]
K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979

का० आ० 1061.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महाधिरक्षक के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना सं० 1(8)/विशेष

सैल/77-एस० एस०-II द्वारा हरियाणा राज्य के लिए नियुक्त सहायक महाभिरक्षक को महाभिरक्षक की निम्न शक्तियां सौंपता हूं।

(i) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

(ii) अधिनियम की धारा 10(2)(o) के अधीन किसी भी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की शक्तियां।

(iii) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियमावली, 1955 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्ति।

इससे दिनांक 20-7-78 की अधिसूचना संख्या 1(8)/विशेष सैल/77-एस० एस-II का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(8)/विशेषसैल/77-एस०एस०-II]
कौशल कुमार, महाअभिरक्षक

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 1st March, 1979

S.O. 1061.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act 1950 (31 of 1950), I do hereby delegate to the Assistant Custodian General for the State of Haryana, appointed vide this Department's notification No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II, dated the 1st March the following powers of the Custodian General.

(i) Powers under Section 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2)(O) of the Act.

(iii) Power of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1955.

This supersedes notification No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II dated 20-7-1978.

[No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II]
KAUSHAL KUMAR, Custodian General.

नई दिल्ली, 1 मार्च 1979

का०आ० 1062.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950(1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी०पी० गुप्ता को, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सहायक महाअभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये निष्क्रांत सम्पत्ति के सहायक महाभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है। इससे दिनांक 20-7-78 की अधिसूचना सं० 1(8)/विशेष सेल/77-एस०एस०-II का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(8)/वि०सै०/77-एस०एस०-II]

New Delhi, the 1st March, 1979

S.O. 1062.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri D. P. Gupta, Joint Secretary in the Rehabilitation Department of the State Government of Haryana, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging he duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act. This supersedes the notifica ion No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II dated 20-7-1978.

[No. 1(8)/Spl. Cell/77-SS. II]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1979

का० आ० 1063—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के संयुक्त सचिव को, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा बंदोबस्त आयुक्त को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, हरियाणा राज्य में बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है। इस अधिसूचना से दिनांक 23-7-1975 की अधिसूचना संख्या 1(14)/वि०से०/75-एस०एस०-II का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(14)/वि०से०/75-एस०एस०-II]
दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 3rd March, 1979

S.O. 1063.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary in the Rehabilitation Department of the Government of Haryana as Settlement Commission in the State of Haryana for the purpose of performing the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act. This Notification supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS. II dated 23-7-1975.

[No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS. II]
D. N. ASIJA, Jt. Director.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1979

का०आ० 1064.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, जयपुर के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निदर्शित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के निदर्शित करती है।

अनुसूची

"19-10-64 को हुए द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.8 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए क्या सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर डिवीजन के प्रबंधतंत्र द्वारा निम्नलिखित कर्मकारों की, उनके नाम के सामने यथा उल्लिखित अस्थायी सेवा को उनकी परिवीक्षा अवधि में गिनती किया जाना और अस्थायीसेवा की उक्त अवधि को हिसाब में लेते हुए उन्हें वार्षिक वेतन-वृद्धियां न दिया जाना न्यायोचित है;

1. श्री एस० एल० टाक, पाली शाखा, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 5-9-1969, से 6-8-70 तक

2. श्री आर० एस० शर्मा, जलोरीगेट शाखा, जोधपुर, 17-3-1969 से 29-8-1969 तक

3. श्री एस० आर० अग्रवाल, चांदपोल बाजार शाखा, जयपुर, 5-6-70 से 11-8-1970 तक यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?"

[सं० एल-12011/100/78-डी-2-ए)]
एस० के० मुकर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1979

S.O. 1064.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India, Jaipur and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers, it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narayan Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Keeping in view the provisions of para 20.8 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 whether the management of Central Bank of India, Jaipur Division is justified in not counting the temporary service of following employees as mentioned against each towards their period of probation and in not granting their annual increments by taking into account the said period of temporary service :

1. Shri S. L. Tak, Pali Branch, Central Bank of India, from 5-9-1969 to 6-8-1970.
2. Shri R. S. Sharma, Jalorigate Branch, Jodhpur, from 17-3-1969 to 29-8-1969.
3. Shri S. R. Agarwal, Chandpole Bajar Branch, Jaipur from 5-6-1970 to 11-8-1970.

If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. L-12011/100/78-D. II.A.]

S. K. MUKERJEE, Under Secy.

New Delhi, the 9th March, 1979

S.O. 1065.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tetturiya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th March, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No 18 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Tetturiya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—None.
For the Workmen—None.

State : Bihar. Industry : Coal.

Jabalpur, dated 27-2-1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/6/78-D. III(A), dated, the 4th August, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Tetturiya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad, in terminating the services of Shri Mahru Singh, Night Guard, with effect from the 1st February, 1977, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The parties filed a settlement on 15-2-1979. The terms of settlement appear to be fair and proper. The award is given in terms of settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Reference 18 of 1978

Employers in relation to the management of Tetturiya Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited

AND

Their workman

PETITION OF compromise.

The above reference has been settled between the parties on the following terms :—

1. That the concerned workman, Shri Maharoo Singh, Night Guard whose services were terminated on Medical grounds with effect from 1-2-77 will be taken back into service with immediate effect at Teturiya Colliery of Govindpur Area.
2. That Shri Singh will be paid 50 per cent of his back wages for the period he remained idle from 1-2-77 till the date of his joining duty.
3. That Shri Singh shall retire from service as per date of birth recorded in the Colliery records.
4. That the entire period of his absence will be treated as on leave without pay and the period from 1-2-77 till the date of his joining shall count towards his gratuity.

That since the above terms are fair and reasonable, the parties pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to give its Award in terms of the above compromise.

For & on behalf of the employers.

J. R. VARMAN, Dy. Personnel Manager,
B.C.C.L.
Security Hqrs., Jealgora.

B. PRASAD, Sr. Personnel Officer,
B.C.C.L.
Security Hqrs., Jealgora.

For & on behalf of the workman

Shri SHANKAR BOSE, Secy.
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

Signature of the concerned workman

Shri MAHAROO SINGH

Dated : the 15th February, 1979.

[No. L-20012/6/78-D. III(A)]

S.O. 1066.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Power House, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, and Shri Allauddin, General Mazdoor, which was received by the Central Government on the 7th March, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference Under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 57 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Power House, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Narsingh, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Jabalpur, dated the 27th February, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/221/75-D-III(A), dated 15-3-1976, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Power House, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad in terminating the services of Shri Allauddin, General Mazdoor with effect from 27th February, 1975 is justified ? If not, to what relief he is entitled ?"

2. It is not disputed that Badlu Mia was an Onsetter in 6&7 Pits of Jamadoba Colliery. His wife Smt. Huzra was a power house kamin. They had two sons namely Razzaque and Allauddin. Former was elder to the latter. On 20-3-1947 Razzaque also got an employment in the same Pits where his father was. Badlu Mia died and when his widow was nearing her retirement she applied for the service being given to her son Allauddin. She was promised that Allauddin shall be enrolled in the register of dependents of the employees maintained by the company and shall be given a job when his turn comes provided no other dependant of the lady was in the employment of the company. Accordingly Allauddin signed his declaration and was appointed as General Mazdoor in the Jamadoba power house on 4-5-74. He was again employed in the same capacity on 21-11-74 and again his service was terminated on 27-2-75.

3. The case of the workmen is that both the times his services was illegally terminated. He was appointed against a permanent nature of work and was a permanent employee. His brother had been in the service on his own strength and not on the basis of his father's service. The management's case that only one member of the family could be in the employment on the basis of relationship was quite baseless, as even he had come under the employment of the company long after the retirement of his mother.

4. The case of the management is that Abdul Rajak had already been inducted into the service of the company as Onsetter/Banksman at 6&7 Pits of Jamadoba Colliery on the basis of relationship. This fact was supressed by Allauddin when he made and signed the declaration. According to the terms when the facts came to light the declaration was found to be false hence the service of Allauddin was terminated. He was a casual labour and had not acquired any temporary or permanent status. He was not working against any permanent vacancy. Casual labours do not automatically acquire the permanent status nor did he complete three months period on any particular job.

5. The Recruitment policy for the casual labour came into effect from 1-11-1973 vide Ext. M-6.A. Abdul Rajak had admittedly joined the employment in the year 1947. There is nothing to show that this or any such employment scheme of dependent was then inforce. It is therefore held as not proved that Abdul Rajak had entered the service as a dependent of his father, who had by then completed hardly, 4 years service when even the present scheme requires 15 years seniority, as minimum for eligibility to the benefits of the scheme.

6. The scheme Ext. M-6 no where says that if any brother or other member of the family of a worker is already in employment then his or her dependent shall not be registered for recruitment as casual worker on that basis of relationship. However, inference is sought to be drawn from some declaration which it is said the workers are required to give that no other son or own brother of the workmen is under employment of the company. No such declaration appears on the record in the present case. Ext. M-1 does not mention any such declaration that no other member of family of Allauddin or Hazra Kamin was in the employment of the company. The letter Ext. M-4 which laid down the condition that the employment of her son will be considered only if none of her dependent had so far been employed by the company was addressed to Smt. Hazra and not to Allauddin. There is no such contract in writing or can be presumed even by implication from the correspondence between the company and Allauddin or even with his mother in which he or she had given any such declaration, assurance or understanding, that his brother or her son was not already in the employment of the company. Thus there is no evidence that any such false declaration assurance or understanding was given by the workman Allauddin or his mother according to the term of which Allauddin's service could be terminated. The scheme as such does not lay down any such condition.

7. Sri S. K. Kar MW-1 said that it was subsequently discovered that Allauddin's brother Abdul Rajak was already in service on the basis of relationship with his father Badlu Mia, therefore, Alauddin was not given any further employment as if his service was terminated in normal course and thereafter he was not given further employment, but the pleadings do speak of termination of service for this reason.

8. It is not proved that Abdul Rajak entered into the service on the basis of his relationship with his father as stated above and there was no question of granting that benefit twice when Alauddin was employed. There is nothing in the scheme to warrant the assumption of Sri Kar that benefit could not be conferred second time. However as discussed above there was thus no question of giving that benefit of relationship to a second member of the family. The reason given by the management for the termination of the service was not adequate.

8. However, Alauddin was only a casual workman. This fact is specifically mentioned in his service cards Ext. M-7 to Ext. M-9. That is clear from the Ext. M-1 declaration also. Standing Orders do not say that there shall be only three categories of employees namely probationer, temporary and permanent. They only lay down the service conditions of those three types of employees and are silent about the category and service conditions of casual employees. This does not mean that no person could be employed on casual terms. He did not complete 12 months and 240 days in service, hence protection of S. 25F was not available to him. He was not a permanent employee and by mere completion of 3 months service as casual employee he would not automatically acquire a permanent status looking to the definition of permanent employee in the Standing Orders.

9. The aforesaid reason for retrenchment being unjustified as held above, the employer was bound to follow the mandate of S 25G but, there is nothing on record to show what 'last come first go' rule was not followed.

10. Once the retrenchment did not suffer from any legal locuna which could invalidate it, the question of giving further chance of employment was within the discretion of the management. The scheme gave no vested right of employment to a dependant. The fact that others were recruited after the termination of his service was therefore irrelevant.

11. It is therefore held that the termination did not suffer from any legal lacuna. Reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-20012/221/75-D. III(A)]

S.O. 1067.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sijua Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited, Post Office Bhelatand, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th March, 1979.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, DHANBAD (BIHAR)

In the matter of a reference under Section 19(1)(d) of the Indus rial Disputes Act, 1947

Reference No. 84 of 1977

PARTIES : Employers in relation to the Management of Sijua Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P.O. Bhelatand, Distt. Dhanbad (Bihar).

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. N. Johri, B.Sc., LL.M., Presiding Officer.

APPEARANCES :

For Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For Workmen—Shri D. Narsingh, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Distt : Dhanbad.

Jabalpur, the 27th February, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/97/77-D. III.A Dated 21st September, 1977, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Sijua Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited, Post Office Bhelatand, District Dhanbad in stopping Sarvashri Md. Akhtar and Md. Israil, Dragger and Mazdoor respectively of Bee-hive-Coke Oven, Sijua with effect from 24.h May, 1976, is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. It is not disputed that Shri Hanif Mia who was working at the relevant time in Sijua Colliery as Trammer, had a son Md. Israil. After the death of Md. Israil's mother Sri Hanif Mia married Smt. Hasima Bibi who was also in the employment of the same Company as Shale-Picking Kamin. With her Shri Hanif Mia had another son namely, Sri Md. Akhtar. When contract labour was abolished the employer Company evolved a Scheme of employing casual labourers. In that Scheme preference for employment was given to the dependents of the employees. The whole scheme was drafted and circulated amongsts the officers giving guidance as to how the recruitments shall be made and as to how the registers shall be kept recording the names of the dependents of the employees for the purpose of being picked up for casual employment. On 2-2-1976 Md. Israil who had been recorded as he dependent of Sri Hanif Mia was employed as a casual labourer when Sri Hanif Mia and Mohd. Israil signed the declaration that none of the sons or brothers of Sri Hanif Mia are in the employment of M/s Tata Iron and Steel Company Limi'ed. He further declared that if at a later date the statement given by him as above is found to be incorrect the Company shall have the right to terminate not only his services but also the services of his dependent Shri Israil Mia. After vocational training Sri Mohd. Israil was given a letter of appointment to a temporary jobs as Category I Mazdoor in Bee-hive-Coke Oven, Sijua, for a period of three weeks for hea'ing the ovens with effect from 22nd April, 1976, that letter is Ex. W/1.

3. Smt. Hasima Bibi got the name of her son Sri Akhtar Mohd. recorded in the register of dependents. On the strength of that relationship Md. Akhtar was given an employment and on 6-3-1976 i.e. after about a month of Md. Israil's appointment as a casual labourer. In the case of Akhtar Mohd. Smt. Hasima Bibi thumb marked the usual declaration that none of her sons is in the employment of the Tata Iron and Steel Company in any department or colliery and if that sta ement is subsequently found to be incorrect then the management will have a right to terminate not only her service but also the services of Md. Akhtar, her son. This Mohd. Akhtar was again given a letter of temporary appointment as Category I Mazdoor at Bee-hive-Coke Oven, Sijua for heating the Coke Oven from 23-4-1976. The letter was dated 22nd April, 1976. Later on he was still continuing in the temporary service in the aforesaid letter dated 22nd April, 1976. He was again given a let'er of appointment date:l 3-5-1976 for temporarily appointing him as Dragger at the same Coke Oven with effect from 3-5-1976 for a period of six months.

4. The management subsequen'ly discovered that both Akhtar Mohd. and Md. Israil were the sons of the same father, Shri Hanif Mia. Their services were terminated on 24th May, 1976 without any charge or domestic enquiry.

5. The case of the management is that according to the Scheme for the recruitment of the dependents of the employees only one dependent of the employee could seek entry on the basis of that relationship in a family. Thus even when both husband and wife are employed wi h the Company only one of their dependents could be so recruited. Thus they gave false declaration that no other member of the family has been given employment and therefore in the terms of that contract of service which specifically provided that fallacy of declaration will expose them to termination of services, their services were terminated by the management. Later on the management offered that the parents may elect and nominate one of their sons to be kept in service but that offer was rejected by them.

6. The case of the employees is that they had not made false declaration. Their services were not liable to be terminated. They had attained temporary status and termination if necessary could only be done according to the Standing Orders which require a specific charge and enquiry They were employed to work against permanent nature of jobs hence their appointment could not be termed as casual.

7. Believing all that was said by the management to be true I questioned the learned Counsel for the management to show me as to how the declaration given by Sri Hanif Mia for the employment of Mohd. Israil was false. Learned Counsel had no answer to this querry. That declaration was given on 2-2-1976 when Mohd. Akhtar was not in employment. Thus Sri Hanif Mia was making only a true declaration when he stated therein on that date that his no other son or brother was in employment of the Company on that date. Since the declaration was not false the management had no right to terminate the services of Mohd. Israil on the basis of the terms and conditions of service incorporated in the declaration that in the event of declaration being found false on any subsequent date the management will have a right to termina'e his services. Leaving aside the question of temporary status which he had attained and even without considering the impact of the Standing Orders it is undeniable that the management was wholly unjustified in terminating his services.

8. Learned Counsel for the management tried to minimise the gravity of this atrocity committed by the management on Mohd. Israil by saying that an option had been given to the parents to elect and nominate one of their sons for being kept in service. Such an offer could not minimise the gravity of the action so taken by the management because in his own rights Md. Israil was entitled to continue in service. His retrenchment was wholly illegal and void and there was no question of leaving his fate to the election of his paren'ts for nominating one of the two step brothers for being kept in service. No further discussion is necessary so far as his case is concerned.

8. In the case of Mohd. Akhtar the declaration was signed by Smt. Hasima Bibi that none of her sons or own brother were in the employment of the Company. When this declaration was signed on 5-3-1976 Mohd. Israil was already in service. He was not her son. There is nothing to show that the word 'son' used in the declaration was to include a step son also. Thus there was no fallacy in her declaration as well. He had also attained the temporary status and his service could not be terminated without a proper charge under Standing Orders. The rest of the arguments as given in the previous case of Mohd. Israil applied to this case as well and therefore I am of the view that the termination of the services of Mohd. Akhtar was wholly illegal and void.

9. I have gone through the Scheme. It has no statutory sanction. The scheme nowhere mentions that if both husband and wife are in service only one of their dependents shall be entitled to be recruited on the strength of relationship. On the other hand, the Scheme mentions to the contrary that each worker shall have a right to get his dependent registered for recruitment in the register of deptndents. When both husband and wife are in employment each one has his right to get his or her dependent registered. Already exploded English Theory of unity of personality between husband and wife does not apply in the present case. The scheme never talks of a family and there is no justification for denying the right to one of the two workers whether they are related to each other as husband and wife or not. Thus the notion developed by the managing personnel of the Company that the scheme is for entertaining only one of the dependents from a family is not a correct notion and is not warranted by the clauses of the Scheme.

10. I have been asked to read this implied condition of one member from a family from the language used in the declaration form but I am sorry to say that even that language does not warrant such an inference. The form requires the employee to make a declaration that none of his or her son or own brother is in the employment of the Company. As discussed above there can be two different sons of the two different employees related to each other as husband and wife just as step son and simnarly the brother of the husband and brother of the wife cannot be deemed to be the members of the same family and yet the two will have a right to get employment on account of that relationship one as husband's brother and the other as the wife's brother. In this way I am of the view that the Scheme nowhere provided that only one of the members of the family *shall be entitled to enter into the service as casual labourer* on the basis of the relationship.

11. Moreover the Scheme is applicable only to the casual workers. Once that worker has crossed the stage of casual employment and has entered into the arena of Temporary *employment the Scheme becomes wholly inapplicable to him.* He is then covered by the Standing Orders as the terms and conditions of his service and the employment of such an employee cannot be terminated without resorting to the provisions of the Standing Orders which require the framing of the charge and a proper enquiry.

12. The misconducts defined in Clause 19 of the Standing Orders do not cover the present situation. Even according to the employers witness which has specifically that Subclause (17) of Clause 19 will not cover the present declaration even if they are false in the sense of suppressing that no other member of the family was in employment because Clause 17 only says that giving of false information regarding his name, age, father's name, qualifications or previous service at the time of employment would be a misconduct. In the declaration there was no fallacy with respect to any of *the aforesaid particulars given at the time of employment.* Thus under Standing Orders none of these two employees committed any misconduct and the management was therefore unable to frame any charge against them.

13. In the limited analysis it is held that the management was not justified in stopping the two employees from work with effect from 24th May, 1976. They shall be deemed to have continued in service till they are reinstated back to the post which they held on 24th May, 1976 and shall be entitled to all wages and other allowances for this intervening period. The *management shall further pay* Rs. 100 as costs for driving these innocent employees to this litigation. Award is given accordingly.

Dated : 27-2-1979.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-20012/97/77-D.III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1979

संदेश

का० आ० 1068.—भारत सरकार के पूर्वतन श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के अधिसूचना का० आ० संख्या 3453, दिनांक 22 सितम्बर, 1967 द्वारा गठित श्रम न्यायालय जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है; के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री डी० एस० पारोपकारी को पूर्वोदित गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं० एस० 11020/1/79/डी 1(ए)]

एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 12th March, 1979

S.O. 1068.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Nagpur, constituted by the Notification of the Government of India in the then Ministry of Labour Employment and Rehabilitation No. S.O. 3453 dated the 22nd September, 1967;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri D. S. Paropkari, as the Presiding Officer of the Labour Court constiuted as aforesaid.

[No. S. 11020/1/79/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer.

New Delhi, the 12th March, 1979

S.O. 1069.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th March, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY.

Reference No. CGIT-2/9 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of AIR India

and

Their Workmen

APPEARANCES

For the Employers	: Shri S. D. Vimadalal, Counsel.
For the Workmen	: Shri C. L. Dudhia Counsel.
For M/s. Mehrotra and C.M. Mathews,	: Shri V.T. Taraporevala. Counsel.

Chief Technical Instructors

Industry : Air Lines,

State : Maharashtra.

Bombay, dated the 21st February, 1979.

AWARD

1. The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their order No L-11011/7/72-LR.III dated 6-4-1972.

(i) Having regard to the duties, functions, responsibilities and status of Manager-Flight Engineering, Manager-Technical Training, Chief Flight Engineers,

Chief Technical Instructors and Technical Instructors, whether the claim of the Indian Flight Engineers' Association for a common inter-se seniority list of holders of the above-mentioned posts and the posts of Flight Engineers for purpose of conversion training and matters incidental thereto is justified?

(ii) Whether the appointments of Sarvshri U. Mehrotra and C. M. Mathews to the posts of Technical Instructor and subsequently to the posts of Chief Technical Instructor are proper and justified under the promotion procedure laid down by the Corporation ? If not, to what relief, if any, are the other affected Flight Engineers entitled ?

2. On behalf of the workmen the General Secretary of the Indian Flight Engineers' Association which is a registered trade union has filed a statement of claim, Regarding item No. 1 of the dispute set out in the schedule, their case is that Flight Engineers promoted to the posts of 1. Manager, Flight Engineering, 2. Manager, Technical Training, 3. Chief Flight Engineer, 4. Chief Technical Instructor and 5. Technical Instructor do not cease to be Flight Engineers on their promotion and therefore as per their seniority among the Line Flight Engineers they should be sent for conversion training, i.e. from Boeing 707 to Boeing 747. They say that persons holding the aforesaid five categories of posts should not be alowed to supersede the other Line Flight Engineers senior to them. The management having accepted this principle at a joint meeting held on 22-3-1970 is said to have ignored the same in selecting Shri U. Mehrotra, Chief Tchnical Instructor for conversion training superseding his senior Shri P. K. Gupta. They submit that the Management's contention that the Chief Technical Instructor holds an executive post and therefore falls in a different category is not justified. Therefore, they demand a common interseniority of Flight Engineers including the so called Executive Flight Engineers and on the basis of such common seniority personnel for conversion training should be selected. The other dispute relates to the appointment of M/s. U. Mehrotra and C. M. Mathews to the posts of Technical Instructors and subsequently to the posts of Chief Technical Instructors. According to the Union after the publication of the Award of Shri G. D. Khosla, National Industrial Tribunal laying down terms and conditions of service of the various categories of workmen employed by M/s. Air India including Flight Engineers, Flight Engineering Instructors, Chief Flight Engineer and Cadet Flight Engineer, the Association raised a dispute in February, 1966 regarding emoluments and terms and conditions of service of the Chief Flight Engineer, Chief Technical Instructor, Assistant Chief Flight Engineer and Technical Instructor who were all members of the association at that time. The management after discussing the matter with the Union for some time repudiated the Union's claim to represent the cause of Executive Flight Engineers on the ground they held managerial posts. The Association took up the matter with the management. Meanwhile recruitment to the posts of Technical Instructors was made in July, 1966 and M|s. K.K. Velu, J. Gopalakrishnaiah and Shri Vasudeva were selected to those posts. When the management stipulated that their selection to those posts was subject to their disassociating themselves from trade union activity they declined to accept the same. Thereafter on 27-11-1967 the management once again invited applications from Flight Engineers having six or more years of experience for the posts of Technical Instructors in the Training Division. After interviewing the several applicants the selection panel selected M|s. Spencer, Sharpe, P. K. Gupta and Pasricha. While issuing letters of appointment to them the management included for the first time clause 4(a) stipulating inter alia that the post of Technical Instructor being an Executive post the selected candidate should not take part in any trade union activity. On seeing this clause the aforesaid four persons requested the management to delete the said clause and keep their acceptance letters in abeyance and to discuss the matter with the association. The management by their letter dated 14-3-1968 stated that it was not possible either to keep the acceptance letters in abeyance or delete the clause as suggested by them. The union contends that the Executive Flight Engineers are also workmen within the meaning of section 2(s) of the Industrial Disputes Act and that the management has no right to restrict their right to pursue genuine trade union activity. M|s. Mehrotra and C.M. Mathews had ceased to be members of the Union from 1966 October and 1964 respectively. The management once again called for applications for the posts of Technical Instructors by their notice dated 22-8-1968. Four Flight Engineers namely M/s. Velu, Mehrotra, Mande and Mathews in the order of seniority applied for the said posts. Mr. Velu in his application requested the management to inform him of the conditions of his service while the other three did not do so. At the interview Mr. Velu was called by the Operations Manager, Training, and asked as to what he meant by requesting the management to let him know the service conditions. Mr. Velu informed the management that he liked to know whether the management would insist on the clause regarding not taking part in the trade union activities being adhered to. The management told him that he could not be considerd for appointment to the post of Technical Instructor if he insisted on deletion of the said clause. At the selection only M|s Mehrotra and Mathews were selected and not the other two persons. The union submits that because of their insistence on the deletion of clause 4(a) restricting their right to participate in trade union activities the said two persons were not selected. That is why the union submits that the selection of M|s. Mehrotra and C. M. Mathews to the posts of Technical Instructors is illegal and that the non-selection of M/s. Velu and Mande because of their insistence on the deletion of clause 4(a) as an unfair labour practice. They further submit that there was no other reason for overlooking the claims of Mr. Velu who is senior to Mr. Mehrotra and Mr. Mande who is senior to Mr. Mathews. The management by their notice dated 25-5-1971 invited applications from Flight Engineers who had completed eight or more years of service as Flight Engineers by 1-6-1971 for the post of Chief Technical Instructor, consequent upon the post falling vacant by Mr. J.J. Spencer, being declared medically unfit. The union submits that six Flight Engineers who were members of the Association had applied for the said post stipulating that their applications might be considered without prejudice to their rights and contentions under the Industrial Disputes Act, and for this reason their applications were summarily rejected. This left only M|s. Mehrotra and Mathews in the field. In between the date of calling for applications and the date of the interview another post of Chief Technical Instructor fell vacant as a result of Mr. Sharpe submitting his resignation. Therefore, both M|s Mehrotra and Mathews were selected to fill in the 2 posts of Chief Technical Instructors. The union questions the validity of this selection also on he ground that it affected the right of its members to pursue trade union activity even while holding the post of Chief Technical Instructors. They call this restriction on their right as an unfair labour practice. This controversy between the management and the union was referred to the Regional Labour Commissioner, Bombay for conciliation. On his submitting a failure of conciliation report the present reference is made to this Tribunal for adjudication. The workmen pray that the action of the management in sending Chief Technical Instructors who are junior to the other Line Flight Engineers for conversion training out of turn is illegal, improper, mala fide, unjustified and amounts to victimisation and unfair labour practice. They further submit that the appointment of M/s. Mehrotra and C. M. Mathews to the posts of Chief Technical Instructors is mala fide and premature and they should not be allowed to have precedence over the other senior Flight Engineers for conversion training.

3. The management filed a preliminary written statement the gist of which is that the seniority of Management|Executive cadres and the seniority of workmen cadres must be necessarily different and must be differently considered for all purposes in the light of the different status, qualifications, functions, duties and responsibilities. With regard to the second issue referred for adjudication it is submitted that the choice for selecting appropriate personnel for the posts of Technical Instructors and Chief Technical Instructors is entirely a managerial function and cannot be called in question by the Union. They also contend that the Executive Flight Engineers do not fall within the definition of workmen under the Industrial Disputes Act. They also submit that there is no irregularity in the appointment of M|s. Mehrotra and Mathews as Technical Instructors in the first instance and thereafter as Chief Technical Instructors by way of promotion. They pray that this reference may be answered against the workmen.

4. On going through the statement of claim, filed by the workmen the management have filed an additional statement,

The workmen also filed a further statement after seeing the additional statement filed by the management.

5. M|s. Mehrotra and Mathews filed a separate written statement adopting the written statement of the management.

6. This dispute was at first referred to CGIT No. 1 who took it on file as Reference No. 3 of 1972. By their order No. L-11011/7/72-LRIII/DII(B) dated 6-5-1977 the Government has transferred this case to the file of this Court.

7. Shri Ramlal Kishan CGIT No. 1 recorded a part of the evidence of EW-1 Shri Kadle, Manager, Flight Engineering and the rest of the evidence by me. Exhibits E-1 to E-122 on behalf of the management and Exhibits W-1 to W-160 for the workmen were marked. After the close of the evidence of EW-1 the parties took time to settle the matter out of Court. On 21-2-1979 both the parties appeared before the Court and filed a Memo. of Settlement admitting the terms thereof. They pray that an Award in terms of the settlement may be passed. On going through the terms of settlement I am satisfied that they are beneficial to the workmen and that an Award should be passed in terms thereof.

. In the result this reference is answered in terms of the settlement arrived at by the parties and embodied in the memo. filed before Court. A copy of the memo. of settlement annexed hereto may be read as part of this Award.

ARD/24-2-1979.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/9 of 1977

BETWEEN

Employers in relation to the Air-India.

AND

Their workmen—Indian Flight Engineers' Association.

May it please the Honourable Tribunal.

Both the parties in the above Reference after mutual discussion regarding the demands under the Reference and matters incidental thereto have arrived at the following terms of an over-all Settlement in pursuance of the Record Note dated 9th February 1979 already signed by the parties and pray that this Honourable Central Government Industrial Tribunal be pleased to make an Award in terms of the said Settlement which is annexed hereto.

Dated at Bombay this 21st day of February 1979.

Indian Flight Engineers' Association	Air-India
Sd/-	Sd/-
P. N. Phadnis	V. N. Malya, Dy. Industrial
Assistant Secretary	Relations' Manager.
Sd/-	Sd/-
C. L. Dudhia,	S. D. Vimadalal, Counsel
Counsel for Indian Flight	for Air-India
Engineers' Association	
	Sd/-
	V. J. Taraporevala, Counsel
	for Mr. U. Mehrotra
	and Mr. C. M. Mathews

ANNEXURE

Terms of Settlement

After considerable discussions, it has been agreed by and between the parties as under :—

(1) At present, all the Line Flight Engineers are in the grade of Rs. 1270-50-1320-60-1500-100-1700. In order to create promotional opportunities for the Line Flight Engineers, it has been agreed that the grade of Rs. 1440-60-1500-100-1900 will be extended to the category of Line Flight Engineers. The existing Line Flight Engineers who have reached the maximum of their grade prior to 1966, will be promoted to the grade of Rs. 1440-1900 as one time exercise. The number of such Flight Engineers as on date, is 21. This will be given effect at the time of finalisation of current wage negotiations.

(2) It is agreed that, in future the strength of the Flight Engineers in the grade of Rs. 1440-1900, will be 20 per cent of the Line Flight Engineers. This percentage may be reviewed in future.

(3) The additional criteria of promoting Flight Engineers from the grade of Rs. 1270-1700 to the grade of Rs. 1440-1900 will be :—

(i) The Line Flight Engineers should have a minimum experience of 10 years as a Flight Engineer in Air-India.

(ii) The Line Flight Engineer should have reached the maximum in the grade of Rs. 1270-1700.

(4) The Indian Flight Engineers' Association raised the question of common inter-se-seniority list of Manager-Flight Engineering, Manager-Technical Training, Chief Flight Engineers, Chief Technical Instructors, Technical Instructors and Flight Engineers for the purpose of conversion training on new equipment. After discussion, it is agreed that the dispute does not exist at present and no Orders are called for.

(5) The Indian Flight Engineers' Association stated that one of the reasons for Line Flight Engineers' reluctance to apply for executive posts, is the present stipulation preventing reversion of Executive Flight Engineers to Line after confirmation. The Indian Flight Engineers' Association representatives were informed that subject to adequate availability of Executive Flight Engineers, and taking into consideration the period required for appointing and training of Executive Flight Engineers, such Executive Flight Engineers wishing to revert back to Line will be permitted to do so after completion of 4 years in the executive cadre.

(6) It is agreed that Manager-Flight Engineering, Manager-Technical Training, Chief Flight Engineer and Chief Technical Instructor are executive posts and that they will not take part in any Trade Union activities. However, they can be members of professional bodies like Indian Flight Engineers' Association for professional activities.

(7) It is agreed that Technical Instructors can continue to be members of the Indian Flight Engineers' Association; however, the Indian Flight Engineers' Association would not issue any directive to the Technical Instructors which would affect their instructional assignment, except in the circumstances wherein an industrial action has taken place involving the Line Flight Engineers and Technical Instructors.

(8) The Indian Flight Engineers' Association representatives were informed that a grade between Sr. Flight Engineer and the Manager-Flight Engineering, will be created for executive Flight Engineers. This will be given effect at the time of finalisation of current wage negotiations.

2. In view of this overall Settlement, the Indian Flight Engineers' Association does not press the Demand No. 2 of the above Reference.

Dated at Bombay this 21st day of February 1979.

Indian Flight Engineers' Association

Sd/-

P. N. Phadnis,
Assistant Secretary.

Sd/-

C. L. Dudhia,
Counsel for Indian Flight Engineers' Association

Air-India

Sd/-

V. N. Malya,
Dy. Industrial Relations Manager.

Sd/-

S. D. Vimadalal,
Counsel for Air-India

Sd/-

V. J. Taraporevala
Counsel for Mr. U. Mehrotra and Mr. C. M. Mathews

[No. L-11011/7/72-I.R. III/D. II(B)]
HARBANS BAHADUR, Desk Officer.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

का० आ० 1070.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 के नियम 3 के साथ पठित कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री एस० एन० पाण्डे, एस० आर० धर और ओ० महिपति के स्थान पर सर्वश्री एस० के० चौधरी, आर० एस० मूर्ति और एस० डी० चन्द्रा को उक्त धारा के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1264, तारीख 5 अप्रैल, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 7, 8 और 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"7. श्री एस० के० चौधरी,
महाप्रबंधक (कार्मिक)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ।

8. श्री आर०एस० मूर्ति,
महाप्रबंधक (कार्मिक)
सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ।

11. श्री एस०डी० चन्द्रा,
कार्मिक खण्ड का प्रधान,
कोल इन्डिया लिमिटेड ।"

[सं० यू-23018/20/78-डब्ल्यू० ए० एम०]
जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1979

S.O. 1070.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947) read with rule 3 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, the Central Government hereby nominates Sarvashri S. K. Choudhury, R. S. Murthy, and S. D. Chandra, as members of the Advisory Committee constituted under the said section vice Sarvashri S. N. Pandey, S. R. Dhar and O. Maheepathi and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, number S.O. 1264 dated the 5th April, 1975, namely :—

In the said notification, for serial numbers 7, 8 and 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted namely :—

"7. Shri S. K. Choudhury,
General Manager (Personnel)
Bharat Coking Coal Limited.

8. Shri R. S. Murthy,
General Manager (Personnel)
Central Coalfields Limited.

11. Shri S. D. Chandra,
Chief of Personnel Division,
Coal India Limited."

[No. U-23018/20/78-WAM]
JAGDISH PRASAD, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1977

का० आ० 1071.—ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डाकघर, उखरा जिला बर्दवान, की बंकोला क्षेत्र के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कोलियरी मजदूर यूनियन (इंटक), जिला बर्दवान करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति के केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 6 मार्च, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री एस० के० आचार्य, ए० सी० पी० ओ०, ई० सी० एल० का बंकोला क्षेत्र

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री सी० एस० बनर्जी, संयुक्त महामंत्री, कोलियरी मजदूर यूनियन

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री० डी० वी० रामचन्द्रन, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(1) क्या श्री जगदीप सिंह, फैन खलासी का 4-9-78 से 19-2-79 तक खाली रहने की अवधि के लिए वेतन का दावा न्यायोचित है । यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

(ii) श्री एस० के० मित्रा, महाप्रबन्धक, बंकोला क्षेत्र, ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड डाकघर-उखरा, जिला बर्दवान। —नियोजक

श्री सी० एस० बनर्जी, संयुक्त महामंत्री, कोलियरी मजदूर यूनियन, डाकघर-उखरा, जिला बर्दवान। —यूनियन

(iii) श्री सी० एस० बनर्जी, संयुक्त महामंत्री, कोलियरी मजदूर यूनियन (इंटक), डाकघर-उखरा, जिला बर्दवान। —यूनियन

(iv) 14,500 कर्मकार

(v) 1 (एक)

मध्यस्थ अपना पंचाट इस करार के समुचित सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०/- (एस० के० आचार्य) ह०/- (सी० एस० बनर्जी)
तारीख 19-2-1979

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

साक्षी :

1. ह०/- (एस० के० मुखोपाध्याय) ता० 19-2-1979,
आशुलिपिक, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, रानीगंज।

2. ह०/- (शिवपूजन सोनार)
एक्सप्लोसिव कैरियर, तिलाबोनी कोलियरी, डाकघर-उखरा, जिला बर्दवान।

मैं मध्यस्थ बनने के लिए सहमत हूं।

ह०/- (डी० वी० रामचन्द्रन) तारीख 19-2-1979.
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी) आसनसोल।

[सं० एल-19013(6)/79-डी० 4(बी)]

नन्द लाल,
डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 17th March, 1979

S.O. 1071.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bankola Area of Eastern Coalfields Limited, Post Office, Ukhra Distt. Burdwan and their workmen represented by the Colliery Mazdoor Union (INTUC), District Burdwan.

And whereas the said management and their wrokmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement, which was received by the Central Government on 6th March, 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing the employer(s).—Shri S. K. Acharyya, A.C.P.O. Bankola Area of ECL.

Representing the workman.—Shri C. S. Banerjee, Jt. Genl. Secretary Colliery Mazdoor Union.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri D. V. Ramachandran, Regional Labour Commissioner(C) Asansol.

(i) Whether the claim of the wages of Shri Jagdip Singh, Fan Khalasi for the period of idleness from 4-9-78 to 19-2-79 is justified; If so to what relief is the workman entitled?

(ii) Shri S. K. Mitra, General Manager, Bankola Area, Eastern Coalfields Limited, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.—Employer.

Shri C. S. Banerjee, Jt. General Secretary, Colliery Mazdoor Union, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.—Union.

(iii) Shri C. S. Banerjee, Jt. Genl. Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC) P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.—Union.

(iv) 14,500 workmen.

(v) 1 (One).

The arbitrator(s) shall make his award within a period of three months from the date of publication of this agreement in the official Gazette by the appropriate Govt, or within such further time as extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties :

Sd/- Sd/-
(S. K. ACHARYYA) C. S. BANERJEE
dt. 19-2-1979
Representing the employer Representing the workman

Witnesses :

1. Sd/- (S. K. Mukhopadhyay) Dt. 19-2-79.
Stenographer, Office of ALC(C) Raniganj.

2. Sd/- (Sheopujan Sonar)
Explosive Carrier, Tilaboni Colliery P.O. Ukhra, Dt. Burdwa.

I consent to be Arbitrator.

Sd/- (D. V. Ramachandran) Dt. 19-2-1979.
Regional Labour Commissioner(C) Asansol.

[No. L-19013(6)/79-D.IV(B)]

NAND LAL, Desk Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979